बदलती राहें

Gunjan

वर्ष 01, अंक 29
धर्मशाला, सोमवार, 14 सितंबर 2015

हिमाचल प्रदेश सरकार ने नशे के खिलाफ छेड़ा विशेष अभियान

● मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने किया उच्च स्तरीय कमेटी का ऐलान

प्रदेश सरकार ने नशे के खिलाफ अभियान छेड़ने का ऐलान किया है। यह ऐलान स्वयं मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने किया है। उन्होंने पिछले दिनों जिला कांगड़ा के इंदौरा में जनसभा के दौरान नशे के खिलाफ सरकार की मंशा जाहिर की। ज्ञात रहे कि पंजाब की सीमा के साथ सटे इस क्षेत्र के युवा नशीले पदार्थों की तस्करी और नशाखोरी में संलिप्त पाए गए हैं। यहां पहले देसी शराब की परंपरागत पैदावार होती थी, मगर कुछ सालों से यहां ड्रग्स के कारोबारियों ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं। इस कारण यहां के अधिकतर युवा हिरोइन, चरस, अफीम व इसी प्रकार के नशीले पदार्थों की तस्करी में संलिप्त हो गए हैं। इससे प्रदेश सरकार की चिंता बढ़ गई है। इतना ही नहीं यहां की महिलाओं ने भी इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा है।

पिछले दिनों अपने प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इंदौरा में कहा कि प्रदेश में ड्रग माफिया के विरूद्ध राज्य स्तरीय अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में कार्यरत कानून कार्यान्वयन एजेंसियों से और सतर्कता के साथ नशे के धंधे में संलिप्त लोगों पर शिकंजा कसने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्र विरोधी तत्वों की युवाओं पर नजर रहती है। वे उन्हें नशाखोरी में धकेलकर समाज की भावी पीढ़ी को खोखला करने की कोशिश करते हैं। हिमाचल में किसी कीमत पर यह नहीं होने दिया जाएगा।

इसके बाद मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शिमला में नशे के खिलाफ एक उच्च स्तरीय कमेटी के गठन का ऐलान किया है। उन्होंने वन और राजस्व विभागों को निर्देश दिए कि वे यह सुनिश्चित बनाएं कि लोग सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से भांग और पोस्त की खेती न करें। उन्होंने कहा कि पुलिस शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना एवं जन संपर्क, कृषि, बागवानी विभागों को शामिल कर एक प्रदेश में नशाखोरी की समस्या से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी, जो युवा पीढ़ी को नशे से बचाने व नशे की समस्या के समाधान के लिए एक ठोस योजना प्रस्तुत करेगी।

मुख्यमंत्री ने नशे के धंधे में संलिप्त लोगों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस अधिकारियों के एक समर्पित दल के साथ अलग पुलिस अधीक्षक कार्यालय आरम्भ करने का सुझाव दिया। वीरभद्र सिंह आज प्रदेश में नशाखोरी की समस्या से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि पंचायतों को उनके अधीन आने वाले क्षेत्रों में निजी या सरकारी भूमि पर किसी प्रकार के नशे की अवैध खेती के सन्दर्भ में सूचना देने का दायित्व सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार या इस तरह की किसी गतिविधि की सूचना देने वाले व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे का अवैध करोबार भारत के साथ-साथ विश्व भर के लिए एक चुनौती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नशे के कारोबार के उन्मूलन के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, लेकिन अभी तक उठाए गए कदम ही पर्याप्त नहीं हैं तथा ये कदम प्रदेश में भांग और पोस्त के उत्पादन के पूरी तरह निर्मूलन और बाहरी राज्यों से नशे के कारोबार को रोकने के लिए काफी नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सतत विकास के साथ-साथ राज्य को पूरी तरह नशामुक्त बनाना हमारी प्राथमिकता है।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि युवाओं का बड़ी संख्या में नशे की गिरफत में आना एक गम्भीर समस्या है और यदि समय रहते इसका समाधान नहीं किया गया तो हिमाचल को भी पंजाब राज्य की तरह समस्या का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने नशे की समस्या के समाधान के प्रति प्रदेश सरकार की वचनबद्धता को दोहराते हुए पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों को भांग और पोस्त की अवैध खेती के निर्मूलन के लिए नियमित छापे मारने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार नशे की समस्या के उन्मूलन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस समस्या को हर कीमत पर रोकने तथा दोषियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई पर बल दिया ताकि न तो प्रदेश में नशे के सामान का उत्पादन हो और न ही यह सामान प्रदेश के बाहर से यहां लाया जा सके। वीरभद्र सिंह ने कहा कि नशे के धंधे में बड़े मुनाफे का लोभ आपराधिक संगठनों को आकर्षित करता है।

उन्होंने कहा कि इन्टरनेट के माध्यम से दवाईयों की अवैध बिक्री प्रमुखता से उभरती समस्या है, जिससे प्रभावी तरीके से निपटने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पाया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों के युवा %साइकोट्रॉपिक ड्रग्स' के आदी हो रहे हैं, जो आसानी से उपलब्ध हो जाती है।

उन्होंने पुलिस द्वारा नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों पर कड़ी नजर रखे जाने की आवश्यकता पर बल दिया। वीरभद्र सिंह ने कहा कि पुलिस को संगठित ड्रग ट्रेड में संलिप्त प्रमुख लोगों पर शिकंजा कसना चाहिए, क्योंकि यह पाया गया है कि वे 18 से 25 वर्ष तक के युवाओं को लालच देकर कुरियर के रूप में उनकी सेवाएं लेते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे की समस्या के समाधान में अध्यापकों को भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए और उन्हें कक्षाओं के बाद भी बच्चों पर नजर रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्कूलों के आस-पास की दुकानों की नियमित निगरानी की जानी चाहिए और यदि ऐसी जगहों पर दुकानदारों द्वारा किसी प्रकार के नशे की अवैध ब्रिकी का कोई सबूत मिले तो इसकी सूचना पुलिस को दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग की नार्कोटिक विंग को मजबूत किया जाएगा और इस समस्या से निपटने के लिए धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने इस अवसर पर पुलिस एवं अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों से सुझाव भी मांगे। राजस्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि वन और राजस्व विभागों द्वारा सरकारी जमीन पर भांग और पोस्त की अवैध खेती पर नजर रखने के लिए एक संयुक्त अभियान चलाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि पुलिस और ड्रग निरीक्षकों द्वारा संयुक्त रूप से संदेहास्पद दवाई की दुकानों, जो युवाओं को बिना डाक्टरी सलाह के और ऊंचे दामों पर युवाओं को दवाइयां बेचते हैं, पर नियमित छापेमारी की जाएगी। इस अवसर पर पुलिस एवं अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

एचआईवी प्रभावित राहुल को सीएससी ने दिखाई राह

एचआईवी प्रभावित महिला से करवाई गई शादी

राहुल 35 वर्षीय युवक है, जो ड्राईवर के का काम करता है। वर्ष 2010 में पहली बार उसे पता चला था कि वह एचआईवी पाजिटिव है। इस बात का पता उसे तब चला जब वह बीमार पड़ा था। जब उसकी बीमारी काबू नहीं आ रही थी, तो डाक्टर ने उसे एचआईवी टेस्ट कारवाने की सलाह दी थी। इस पर जब उसने अपना टैस्ट करवाया तो उसे एचआईवी पाजिटिव होने के बारे में पता चला। यह बात सुनते ही उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसने अपने परिवार को अपने एचआईवी पाजिटिव होने के बारे में नहीं बताया था। वहीं दूसरी ओर अब परिवार वाले भी उस पर शादी करने का दबाव बनाने लगे थे। इस बात की जानकारी होने के बावजूद वह शादी करने को तैयार नहीं था।

वह जानबूझ कर किसी ओर की जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता था। लिहाजा उसने शादी का विचार ही छोड़ दिया था, मगर इस बारे में आपने परिजनों को नहीं बता पा रहा था। इसी उधेड़बुन के बीच में किसी ने उसे कम्युनिटी स्पोर्ट सेंटर में जाने की की सलाह दी। वह सीएससी में आया और यहां तैनात कांउसलर के साथ उसकी लंबी बातचीत हुई। उसने अपनी पूरी बात कांउसलर को बताई कांउसलर ने बात को ध्यानपूर्वक सुना और उसको समझाया कि अगर वह शादी करना चाहता है तो किसी एचआईवी पाजिटिव महिला के साथ शादी कर सकता है। इस पर उसे आशा की किरण दिखाई दी और उसने कहा कि अगर ऐसा हो जाता है तो उसकी सारी समस्या का हल हो जाएगा। दो दिन बाद सीएससी में स्पोर्ट ग्रुप की बैठक आयोजित की गई। इसमें राहुल की शादी को लेकर चर्चा की गई। इसमें अन्य सदस्यों के साथ-साथ राहुल को भी बुलाया गया था। उसके अलावा आठ अन्य लोग भी इस मिटिंग में शामिल हुए। इसी दौरान जब शादी की बात पर मिटिंग में चर्चा चल रही थी तो सरला नाम की 26 वर्षीय विधवा महिला ने भी शादी की इच्छ जाहिर की। एचआईवी प्रभावित सरला इस समय अकेली थी और पिछले चार सालों से दवाई ले रही थी। उसने मिटिंग के दौरान कहा कि अगर कोई एचआईवी पाजिटिव व्यक्ति मिल जाए तो वह भी शादी करना चाहती है। इसी दौरान सदस्यों ने राहुल व सरला को शादी करने का सुझाव दिया। अगले दिन वे आपस में मिले और दो दिन बाद उन्होंने शादी भी कर ली। आज सरला ने अपनी सिलाई-कढ़ाई की छोटी सी दुकान खोल रखी है। वहीं राहुल भी गाड़ी चलाने का काम कर रहा है। उनकी गृहस्थी अच्छी चल रही है। इतना ही नहीं दोनों के परिवार वाले इस शादी से खुश हैं।

एंटीबायोटिक्स का असर लौटाएगी नई दवा

वाशिंगटन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से प्रभावित लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जागी है। शोधकर्ताओं ने एंटीबायोटिक्स के ऐसे नए समूह की खोज की है जो इस परेशानी से पार पाने में मदद कर सकता है। ऐंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वह स्थिति है जिसमें कोई बैक्टीरिया एंटीबायोटिक दवा के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर लेता है।

मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरस (एमआरएसए) एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का सबसे खतरनाक और प्रसारित रूप है। 2013 में एमआरएसए संक्रमण के कारण अमेरिका में 9937 लोगों की मौत हो गई थी। शोध में पाया गया कि नई एंटीबायोटिक दवाएं पारंपरिक एंटीबायोटिक से इस मामले में अलग है कि इनमें ट्रांजिशन श्रेणी की धातु इरीडियम उपस्थित है।

इससे बने तत्व आसानी से विघटित नहीं होते हैं, जो कि किसी एंटीबायोटिक के लिहाज से महत्वपूर्ण गुण है। इरीडियम की मौजूदगी के बावजूद इन दवाओं को जीवों या उनकी कोशिकाओं के लिए जहरीला नहीं पाया गया। वर्जिनिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ता जोसेफ मेरोला ने बताया कि अब तक के शोध में इस दवा को पूरी तरह सुरक्षित पाया गया है। एक अन्य शोधकर्ता ने बताया कि अगले कुछ सालों में इस दवा के और गुणों का पता लगाया जा सकेगा। चूहों पर परीक्षण के बाद शोधकर्ता मानव कोशिकाओं पर इसका प्रभाव जांच रहे हैं।

भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है एंटीबॉयोटिक्स

लंदन। भारत विश्व में एंटीबायोटिक दवाओं का सबसे ज्यादा खपत करता है। पिछले एक दशक में लोगों में एंटीबायोटिक खरीदने की प्रवृति में 62 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। शोध के तहत वर्ष 2000 से 2010 के बीच 71 देशों में एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल का अध्ययन किया गया। वर्ष 2000 में भारत में जहां एंटीबायोटिक की आठ अरब गोलियों का इस्तेमाल होता था वहीं वर्ष 2010 में इसकी संख्या बढ़कर 12.9 अरब हो गई है। ग्लोबल ट्रेंड्स इन एंटीबायोटिक्स कंजम्पशन 2000-2010 शोध के मुताबिक, एक भारतीय एक वर्ष में औसतन 11 एंटीबायोटिक का सेवन करता है।

पिछले एक दशक में दुनियाभर में एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल 36 प्रतिशत बढ़ा है। आर्थिक रूप से वृद्धि कर रहे देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका में एंटीबायोटिक दवाओं का एक तिहाई हिस्सा इस्तेमाल होता है। इन देशों के मध्य वर्ग की क्रय शक्ति में इजाफा हुआ है। जर्नल लेसेंट में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, एंटीबायोटिक्स के अधिक इस्तेमाल से लोगों पर दवाइयों का असर कम होने और दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया के प्रभावी होने की आशंका बढ़ी है। प्रमुख शोधकर्ता थॉमस वान बोकेल ने कहा, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ रही है और वे आसानी से एंटीबायोटिक्स खरीद सकते हैं।

अगर इन दवाओं का प्रभाव समाप्त हो गया तो वास्तव में कुछ नहीं बचेगा। उन्होंने कहा, निम्न और मध्य आय वाले देशों में सेफैलोस्पोरिन और फ्लोरोक्विनोलोन के उपयोग में वृद्धि से साफ पता चलता है कि इन देशों में डेंगू, चिकुनगुनिया जैसी बीमारियों तेजी से फैल रही हैं। इनमें से ज्यादातर बीमारियां वायरस से फैलती हैं जिनपर एंटीबायोटिक्स प्रतिक्रिया करते हैं। लेकिन ज्यादातर देशों में इंफ्लुएंजा के फैलने पर भी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जबकि फ्लू पर ये दवाइयां असर नहीं दिखाती।

पब्लिक रिलेशंस : मिलो-जुलो, बोलो और कमाओ!

पीआर के पाठ्यक्रम में समाहित होता है, आपमें जन-संवाद तथा लोगों के मनोविज्ञान को समझने का कौशल विकसित करना, जोकि सूचनाओं के आदान-प्रदान में सहायक सिद्ध हों। मूलत: इसका उद्देश्य लोगों व उनकी संवाद आवश्यकताओं को समझना होता है।

अधिकांश पाठ्यक्रम जन-संचार पाठ्यक्रम से समानता रखते हैं या उनमें समाहित होते हैं तथा उनमें तमाम तकनीकी ज्ञान के साथ संवाद क्षमता विकसित करने पर जोर दिया जाता है। यहां तकनीकी ज्ञान को सरल बनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है।

अधिकांश जन-संपर्क पाठ्यक्रमों में ये विषय समाहित होते हैं: जन-संवाद से परिचय, भारत में प्रिंट मीडिया का इतिहास, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व फोटोग्राफी, अंतरराष्ट्रीय संवाद व मानवाधिकार, सूचना तकनीक का जन-संपर्क के क्षेत्र में महत्व, मानव आवश्यकताओं व मनोविज्ञान का अध्ययन।

पदार्पण

यदि आप इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको इस कोर्स को संचालित करने वाले कॉलेजों की सूची बनानी पड़ेगी तथा यह भी ध्यान रखना होगा कि कॉलेज का कोर्स कंटेंट कैसा है। जन-संचार पाठ्यक्रमों को संचालित करने वाले कॉलेजों में दाखिला लेना श्रेयस्कर रहेगा चूंकि ये मीडिया प्रोफेशनल्स से संबाद स्थापित करने में सहायक सिद्ध होते हैं। स्कूलिंग के उपरांत आप जन-संचार में स्नातक तथा इसके बाद जन-संवाद में स्नातकोत्तर की डिग्री ले सकते हैं।

इसके अलावा किसी भी विषय में स्नातक करने के बाद भी आप जन-संपर्क में स्नातकोत्तर कर सकते हैं। कुछ संस्थान डिप्लोमा कोर्स भी संचालित करते हैं। इस क्षेत्र के प्रमुख संस्थान हैं: जेवियर इंस्टिट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन मुंबई, सिम्बोयसिस स्कूल पुणे तथा इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ मास कम्युनिकेशन नई दिल्ली।

क्या यह मेरे लिए सही करियर है?

यह जानने के लिए कि जन-संपर्क का करियर आपके लिए सही है अथवा नहीं, आपको यह जानना होगा कि आप लोगों से बात करने में कितने निपुण हैं और आपमें मीडिया के साथ काम करने का कितना जुनून है। यदि आप पढ़ने के शौकीन हैं और दैनिक समाचारों व घटनाओं पर नजर रखते हैं तो जन-संपर्क व जन-संचार का पाठ्यक्रम आपके लिए सही विकल्प साबित हो सकता है। वैसे पीआर कोर्स सभी की संवाद क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है। पीआर प्रोफेशनल्स का वेतनमान बढ़िया होता है।

रोजगार के अवसर

पीआर प्रोफेशनल्स, जिनके पास उत्कृष्ट स्तर की संवाद व लोगों को समझाने की क्षमता है, के लिए विभिन्न उद्योगों में अपार संभावनाएं हैं। विज्ञापन एजेंसियां व मार्केटिंग कंपनियां अच्छे पीआर प्रोफेशनल्स की तलाश में हमेशा रहती हैं। कई पीआर प्रोफेशनल्स पीआर कोर्स करते हुए फोटोग्राफी अथवा विजुअल कम्युनिकेशन में भी कोर्स कर लेते हैं जिससे उन्हें फिल्म-मेकिंग कंपनियों में आसानी से अच्छी जॉब मिल जाती है।

मार्केट वॉच

पीआर प्रोफेशन का विकास पिछले कुछ वर्षों में अद्वितीय रहा है। नित नए टीवी चैनलों, न्यूज चैनलों, आईटी कंपनियों, बीपीओ/केपीओ के खुलने के कारण पीआर प्रोफेशनल्स की मांग उच्चतम स्तर पर है। होटल, शिपिंग एवं लॉजिस्टिक्स जैसे दूसरे क्षेत्रों में भी पीआर प्रोफेशनल्स की बहुत मांग है। पिछले कुछ दशकों में एड एजेंसियों का भी अतुल्यनीय विकास हुआ है। विभिन्न सरकारी विभागों व कंपनियों में जन-संपर्क अधिकारी बनना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है।

सीवी तैयार रखिए, आ रही नौकरियों की भरमार

वैश्विक स्तर पर भारतीय एम्प्लॉयर्स दिसंबर 2015 के अंत तक चौथी तिमाही में अपने हाइरिंग प्लान्स के लिए उत्साहित हैं। मैनपॉवर एम्प्लॉयमेंट आउटलुक सर्वे के मुताबिक सेक्टर्स जैसे होलसेल, रिटेल, यूटिलिटिस विशेष रूप से लॉजिसटिक्स और ट्रांसपोर्टेशन अगली तिमाही में आक्रामक रूप से हायर किए जाएंगे।

भारत में 41 प्रतिशत से ज्यादा एम्प्लॉयर्स सितंबर में खत्म होने वाली तिमाही की तुलना में चौथी तिमाही में ज्यादा संख्या में नौकरियां पैदा करेंगे। लगभग 5000 एम्प्लॉयर्स को भारत में इस सर्वे में शामिल किया गया था।

होलसेल व रिटेल सेक्टर और ट्रांसपोर्टेशन व यूटिलिटी सेक्टर के एम्प्लॉयर क्रमश: 45 प्रतिशत और 44 प्रतिशत पहले के मुकाबले अगली तिमाही में हाइरिंग बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। क्षेत्रीय दृष्टिकोण से, पूर्वी क्षेत्र में लगभग 42 प्रतिशत एम्प्लॉयर्स आने वाले महीनों में नौकरी चाहने वालों के लिए सबसे अधिक अवसर की आशा है।

मैनपॉवर ग्रुप इंडिया के ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर एजी राव ने कहा कि ई-कॉमर्स क्षेत्रों के लिए श्रम बाजार में अधिक नौकरियां जोड़ने के बड़े अवसर है। शॉपक्लूज.कॉम अपनी 800 की टीम में 1200 कर्मचारी जोड़ने की योजना बना रहे हैं, वहीं स्नेपडील वित्तीय वर्ष 2016 तक 5000 कर्मचारी चाहते हैं। शॉपक्लूज के कोफाउंडर संजय सेठी ने कहा कि आने वाले महीनों में बड़े स्तर पर हाइरिंग होगी। अधिकतर ईकॉमर्स कंपनियां अपनी टीम बढ़ाने की तैयारी में हैं।

वर्ष 2014 की चौथी तिमाही से तुलना करें तो सात इंडस्ट्री सेक्टर में से पांच में एम्प्लॉयर्स के हाइरिंग प्लांस कमजोर हैं। माइनिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के एम्प्लॉयर्स ने ९ प्रतिशत अंक की सबसे उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की, वहीं फाइनेंस, इंश्योरेंस और रियल एस्टेट सेक्टर व सर्विस सेक्टर में ७ और ४ प्रतिशत अंक कमजोर निकले।

अगर 2014 की तीसरी तिमाही के साथ चौथी तिमाही की तुलना करें तो नौकरी देने के इरादे फाइनेंस, इंश्योरेंस और रियल एस्टेट सेक्टर में स्थिर बने हुए हैं।

मैनपॉवर ग्रुप ने 42 देशों और प्रदेशों के 59000 एम्प्लॉयर्स का इंटरव्यू लिया। 42 देशों और प्रदेशों में 36 एम्प्लॉर्य अक्टूबर-दिसंबर समय सीमा के दौरान उनके वेतन में अलग-अलग मार्जिन जोड़ना चाहते हैं।

पीएलए पद्धति के लिए जरूरी हैं इसके सिद्धांतों पर अमल

हम पिछले अंक में पीएलए के बारे में और इसके इस्तेमाल के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इसमें बताया गया था कि पीएलए क्या है, इसका इस्तेमाल कौन कर सकते हैं, पीएलए का इस्तेमाल कब किया जाए, पीएलए को कहां इस्तेमाल किया जा सकता है और पीएलए का इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है। अब हम पीएलए के सिद्धांतों के बारे में जानेंगे।

पीएलए के सिद्धांत निम्न प्रकार से हैं:-

1. सहभागिता
2. स्थानीय ज्ञान और अनुभवों को महत्व देना
3. सशक्तीकरण के प्रति समर्पण
4. समूह विश्लेषण एवं सीख
5. दृश्य एवं मौखिक तकनीकों का मिश्रण
6. अनसुनी आवाजों की तलाश
7. सही सोच और व्यवहार का महत्व

1. सहभागिता

सहभागिता सभी लोगों को उन फैसलों को तय करने में सक्रिय और प्रभावी भूमिका निभाने का अधिकार है, जिनसे उनका जीवन प्रभावित होने वाला है। अकसर ऐसा होता है कि एचआईवी/एड्स प्रभावित लोगों को इस बारे में की जाने वाली स्थानीय कार्रवाइयों में शामिल नहीं किया जाता है। जबकि इस कार्यक्रम के परिणामों का सबसे ज्यादा असर उन्हीं लोगों पर पड़ता है। पीएलए पद्धतियों का इस्तेमाल करने वालों का मानना है कि एचआईवी/एड्स प्रभावित लोगों को इस बारे में होने वाली स्थानीय कार्रवाइयों के हर चरण में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेना चाहिए।

पीएलए का इस्तेमाल करने वालों का मानना है कि एचआईवी/एड्स प्रभवित लोगों को इन कार्रवाइयों में न केवल सक्रिय रूप से बल्कि असरदार तरीके से हिस्सा लेना चाहिए। इनकी सोच व राय को केवल सुनना ही काफी नहीं है, बल्कि उन पर संजीदगी से और पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए।

2. स्थानीय ज्ञान और अनुभवों को महत्व देना

किसी खास समुदाय में एक खास तरह से रहने वालों के पास इस बात की बहुत बढ़िया समझ होती है कि एचआईवी/एड्स से उनके समुदाय तथा जीवनशैली पर क्या असर पड़ रहे हैं। बाहरी संगठनों को चाहिए कि एचआईवी/एड्स पर कार्रवाई करने के लिए वे इस ज्ञान का प्रस्थानबिंदु के रूप में इस्तेमाल करें। स्थानीय लोगों को प्राय: इस बात का सबसे अच्छी तरह पता होता है कि एचआईवी/एड्स से उनका जीवन किस तरह प्रभावित हो रहा है।

राजधानियों में बैठे स्वास्थ्य योजनाकार अकसर इस बात को नजरअंदाज कर जाते हैं कि एचआईवी/एड्स से प्रभावित लोगों के अनुभव योजनाकारों के विश्लेषण और उम्मीदों से बहुत भिन्न हो सकते हैं।

प्रभावित लोग एचआईवी/एड्स को किस तरह अनुभव करते हैं और किस तरह मापते हैं, इससे यह भी तय होता है कि वे उसके बारे में किस तरह कार्रवाई करेंगे। मिसाल के तौर पर, ग्रामीण अफ्रीका की एक गरीब, युवा एचआईवी पाजिटिव औरत के अनुभव वैसे नहीं होंगे जिस तरह के अनुभव से शहरी अफ्रीका की कोई संपन्न, युवा एचआईवी पाजिटिव औरत गुजरती है।

क्योंकि एचआईवी/एड्स के बारे में उनके अनुभव अलग-अलग हैं, लिहाजा उसके बारे में उनकी प्रतिक्रिया भी अलग-अलग रहेगी। एचआईवी/एड्स के बारे में स्वास्थ्य योजनाकारों के विचारों और इससे निपटने के तरीकों में इस जटिलता तथा अनुभवों की विविधता को असर नजरअंदाज कर दिया जाता है।

हरेक के लिए सरल, मानक नुस्खे आजमाना कारगर नहीं रहता है। प्रयासों को असरदार बनाने के लिए जरूरी है कि ये प्रयास खास लोगों की खास जरूरतों को ध्यान में रखकर सोचे जाएं। पीएलए पद्धतियां लोगों को एचआईवी/एड्स से पड़ने वाले जटिल व विविध प्रभावों को अभिव्यक्त करने तथा उनका आकलन करने का मौका देती हैं।

पीएलए पद्धति एचआईवी एड्स के बारे में हर व्यक्ति के अनुभवों को वैध और सही मानती है। इस आकलन के आधार पर पीएलए समुदायों और समूहों को स्वयं ऐसी कार्रवाइयों की रूपरेखा तैयार करने में मदद देता है, जिनकी मार्फत वे एचआईवी/एड्स के बारे में अपने अनुभवों को समझ सकते हैं।

3. सशक्तीकरण के प्रति समर्पण

सशक्तीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्तियों या समूहों की फैसले लेने तथा उनको लागू करने की क्षमता बढ़ाने में मदद मिलती है। एचआईवी/एड्स को संबोधित करने के लिए व्यक्तियों, समुदायों और संगठनों को चार तरह की ताकत विकसित करनी चाहिए:

संसाधन शक्ति:-एचआईवी/एड्स से निपटने के लिए संसाधनों तक पहुंच और उन पर प्रभाव।

ज्ञान शक्ति:- एचआईवी/एड्स से निपटने की समझ।

हैसियत की शक्ति:- अधिकारों और सुविधाओं के बारे में सौदेबाजी की क्षमता तथा एचआईवी/एड्स से निपटने के लिए जिम्मेदारियों को पूरा करने की क्षमता।

व्यक्तिगत शक्ति:- स्वाभिमान और आत्ममूल्य का भाव, एचआईवी/एड्स से निपटने के लिए संसाधनों की मांग करते हुए व्यक्तिगत आत्मसाकार, तथा ज्ञान और हैसियत की शक्ति।

4. समूह विश्लेषण एवं सीख

जब लोग और संगठन मिलजुल कर काम करते हैं, तभी स्थिति की एक मुकम्मल समझ पैदा हो सकती है और सबसे बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। स्थिति की पूरी जटिलता को तभी समझा जा सकता है, जब लोग समूह के रूप में एचआईवी/एड्स के विषय में अपने ज्ञान और अनुभवों का आदान-प्रदान करते हैं। तभी सहभागी यह भी देख सकते हैं कि उनके ज्ञान व अनुभवों में कितनी विविधता है तथा उनके बीच क्या समानताएं हैं। सामूहिक विश्लेषण से एचआईवी/एड्स पर बहस-मुबाहिसा शुरू होता है जिससे समूह को इस बारे में कार्रवाई करने की ओर ठोस प्रेरणा मिलती है।

5. दृश्य एवं मौखिक तकनीकों का मिश्रण

रेखाचित्रों, चित्रों और साझा अनुभवों के जरिए सभी लोगों को जटिल विश्लेषण तथा सीखने की प्रक्रिया में समान रूप से हिस्सा मिलता है। दृश्य टूल्स का इस्तेमाल करने से लोगों को विश्लेषण व नियोजन में सुविधा के अनुसार हिस्सेदारी का मौका मिलता है। ऐसे टूल्स से लोगों को उम्र, जेंडर, संस्कृति, साक्षरता, सामाजिक या आर्थिक स्तर आदि से परे हटकर जटिल विश्लेषण करने में मदद मिलती है। लोग अपनी सुविधा अनुसार खुद को अभिव्यक्त कर सकें, इसके लिए पीएलए में मंचन कलाओं का भी इस्तेमाल किया जाता है। ड्रामा और रोल प्ले, दोनों के साथ सवाल-जवाब व फेसिलिटेशन की प्रक्रिया भी चलती रहती है।

6. अनुसनी आवाजें की तलाश

कई बार कुछ लोग फैसलों में अपनी राय देना नहीं चाहते। इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन कई बार लोग चाहे-अनचाहे उस निर्णय प्रक्रिया से बेदखल हो जाते हैं, जो उनको प्रभावित करने वाली है। ऐसा उम्र, लिंग, यौनिकता, एचआईवी स्थिति, वर्ग, जाति, कम साक्षरता, सामाजिक व आर्थिक स्थिति के कारण हो सकता है। लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए इन सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अकसर देखा गया है कि जो लोग एचआईवी/एड्स से पीड़ित हैं या जिनके सामने इसकी आशंका ज्यादा है, उन्हीं का इन फैसलों में सबसे कम हिस्सा रहता है। पीएलए का एक सिद्धांत यह है कि यदि कोई व्यक्ति एचआईवी/एड्स से प्रभावित है या उसकी आशंका में है और फैसलों में हिस्सा लेना चाहता है तो उसे यह अधिकार जरूर मिलना चाहिए। जो लोग फेसिलिटेट करते हैं, उन्हें इस बात का पता लगाना चाहिए कि ऐसे कौन लोग हैं, जो इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, मगर उन्हें रोका जा रहा है।

7. सही सोच और व्यवहार का महत्व

एचआईवी एड्स प्रयासों में सभी प्रभावितों की सक्रिया और प्रभावशाली हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए पीएलए फेसिलिटेटर्स का रवैया/सोच और व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि वे लोगों को बेदखल करने की बजाय उन्हें प्रक्रिया में शामल कर सकें। यहां सिर्फ यही काफी नहीं है कि कार्रवाइयों में हाशियाई या बेदखल तबकों को शामिल कर लिया जाए। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उन्हें किस तरह शामिल करते हैं।

बाल उमंग के तहत 300 से अधिक बच्चे लाभान्वित हुए

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत कार्यरत गुंजन संस्था द्वारा क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला में चलाए जा रहे बाल उमंग कार्यक्रम को छह माह से भी कम समय में भारी सफलता मिली है। इसी साल 20 अप्रैल को शुरू किए गए इस कार्यक्रम के तहत अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में इलाज के लिए आने वाले बच्चों को बीमारी के दौरान घर जैसा माहौल मुहैया करवाकर उनका दर्द कम किया जाता है। अब तक इस कार्यक्रम के तहत तैयार किए गए वार्ड में 300 से अधिक बच्चों को लाभान्वित किया जा चुका है। इस दौरान बच्चों के लिए खास तौर पर कार्टून, पेंटिंग व अन्य आकर्षक सामान से सजाए गए इस वार्ड में दर्द या बीमारी से परेशान बच्चों के चेहरे पर खुशी लाने का प्रयास किया जाता है।

यहां तैनात काउंसलर बच्चों को खिलौने, कामिक्स, कहानी की किताबों के अलावा खुद कहानियां सुनाकर उनका मनोरंजन करती हैं। बच्चों को अस्पताल के वार्ड में ऐसा महसुस ही नहीं होने दिया जाता कि वे बीमारी के कारण घर से बाहर अस्पताल की तनाव भरी देखभाल में हैं। उन्हें इलाज के साथ-साथ घर जैसा माहौल दिए जाने से अब तक काफी सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं। अधिकतर बच्चों के अभिभावकों ने इस प्रयास की सराहना की है। साथ ही वे गुंजन के इस प्रयास का आभार जताना भी नहीं भुलते।

आई.ई.सी. मेटिरियल डवेलप्मेंट - पोस्टर श्रृंखला